श्री मंगुभाई पटेल

राज्यपाल, मध्यप्रदेश

का

अभिभाषण

मध्यप्रदेश विधानसभा अधिवेशन

अग्रहायण–पौष, मार्ग शुक्ल 8, शक 1945 भोपाल, बुधवार 20 दिसम्बर, 2023

माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यगण,

1. सोलहवीं विधानसभा के प्रथम सत्र में आप सभी का हृदय से स्वागत, वंदन एवं अभिनन्दन।
2. निर्वाचन, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। मुझे यह कहते हुए गर्व और प्रसन्नता है कि मध्यप्रदेश में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व की सफल पूर्णाहूति के लिए राज्य के सभी सम्माननीय मतदाता, निर्वाचन आयोग, सभी राजनीतिक दल, शासन-प्रशासन तंत्र एवं मीडिया बधाई के पात्र हैं।
3. इस विधानसभा निर्वाचन में मध्यप्रदेश के इतिहास का सर्वाधिक मतदान होना, न केवल लोकतंत्र में जन-जन की प्रबल आस्था का प्रतीक है, बल्कि माननीय मोदी जी की गारंटी, सरकार के कार्यों और संकल्पों के प्रति जनता के अटूट विश्वास का परिचायक भी है। माननीय प्रधानमंत्रीजी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जनता की जिंदगी को बदलने का मिशन पूरी तरह सफल एवं सार्थक सिद्ध हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि चुनाव जीतने से भी अधिक महत्वपूर्ण है जनता का दिल जीतना। मेरी

सरकार हृदय प्रदेश की जनता को अपने हृदय में बसाकर उनके कल्याण के लिए अनवरत कार्य करेगी।

4. मेरी सरकार ने कार्यभार ग्रहण करते ही आजादी के अमृतकाल में प्रदेश की साढ़े 8 करोड़ जनता के लिए विकसित भारत हेतु विकसित मध्यप्रदेश के निर्माण के नये विज़न और नये मिशन पर नई ऊर्जा, नये उत्साह, नये उल्लास, नई उमंग और नये संकल्प के साथ काम करना प्रारंभ कर दिया है। "सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास और सबका प्रयास"- माननीय प्रधानमंत्रीजी के इस मूल मंत्र को लक्ष्य बनाकर मध्यप्रदेश को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प-पत्र-2023, मेरी सरकार ने आत्मसात कर लिया है।

5. माननीय प्रधानमंत्रीजी के गौरवशाली नेतृत्व में विगत साढ़े 9 वर्षों में भारत में "माई-बाप सरकार" के युग की समाप्ति और "सेवक सरकार" के युग का प्रारंभ हुआ है। गरीब और वंचित, एक जमाने में जिनकी कोई पूछ-परख नहीं थी, प्रधानमंत्रीजी उन्हें पूछते भी हैं और पूजते भी हैं। माननीय प्रधानमंत्रीजी ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि देश के गरीब, देश के किसान, देश की नारी शक्ति और देश के युवा ही उनकी नजरों में सबसे बड़े VIP हैं। मेरी सरकार ने भी इससे प्रेरणा लेकर जन-जन के सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख मानने और जनता की

आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संपूर्ण शक्ति के साथ समर्पित भाव से कार्य करने का प्रण लिया है।

6. आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की 140 करोड़ जनता को अपना परिवार माना है और जनता से उनका भावनात्मक रिश्ता इतना प्रगाढ़ है कि आम आदमी को इस बात का पूरा भरोसा है कि मोदी जी की गारंटी ही, हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी है। जहाँ दूसरों की उम्मीदें ख़त्म होती हैं, वहीं से मोदीजी की गांरटी शुरू होती है। यह निश्चय ही प्रसन्नता का विषय है कि जनता के कल्याण और देश को आगे बढ़ाने के शुभ-संकल्प के साथ "विकसित भारत संकल्प यात्रा"का मध्यप्रदेश में 16 दिसंबर से भव्य शुभारंभ हो गया है। मध्यप्रदेश में इस यात्रा की कमान स्वयं यहाँ की जनता ने संभाल ली है। मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी प्रदेश के नगर-नगर और गाँव-गाँव तक पहुंच रही है और प्रदेश की जनता दीप जलाकर, फूल बरसाकर, रंगोली बनाकर और बड़ी संख्या में यात्रा में भाग लेकर उसका उत्साह के साथ स्वागत कर रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम स्वनिधि योजना आदि हितग्राहीमूलक योजनाओं के लाखों लाभार्थी अपनी जिंदगी बदलने के अनुभव सुना रहे हैं, तो दूसरी तरफ

यह यात्रा सभी पात्र हितग्राहियों तक पहुँचने का माध्यम बन रही है, जो योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए थे। मेरी सरकार, इस यात्रा के दौरान केंद्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति को दिलाते हुए शत-प्रतिशत सेचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करेगी।

7. मेरी सरकार के लिए सुशासन केवल एक शब्द नहीं, बल्कि उसके हर अक्षर को सच्चे अर्थों में चरितार्थ करने का मंत्र है। पारदर्शी, उत्तरदायी, त्वरित, संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ कार्य-संस्कृति शासन तंत्र के प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित करना मेरी सरकार का सर्वोपरि लक्ष्य है। यही कारण है कि मेरी सरकार ने कार्यभार संभालते ही 01 जनवरी, 2024 से साइबर तहसील की व्यवस्था को प्रदेश के सभी 55 जिलों में लागू करने का क्रांतिकारी निर्णय लिया है। मेरी सरकार संपदा-2 सॉफ्टवेयर भी संपूर्ण प्रदेश में शीघ्र लागू करने जा रही है, जिसके माध्यम से डिजिटल रजिस्ट्री की प्रक्रिया सरल और सुगम बनेगी।

8. गंभीर अपराधों में लिप्त रहे आदतन अपराधियों को कठोर से कठोर दण्ड दिलवाने तथा ऐसे अपराधियों द्वारा माननीय न्यायालय से प्राप्त जमानत के लाभ के दुरूपयोग को रोकने, अनुपयोगी और खुले बोरवेल से होने वाली दुर्घटनाओं को

सुनियोजित रणनीति बनाकर रोकने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अवैधानिक प्रयोग पर नियंत्रण तथा मांस-मछली के अनियंत्रित क्रय-विक्रय को प्रतिबंधित करने के लिए अभियान के रूप में कार्यवाही प्रारंभ करके मेरी सरकार ने यह स्पष्ट संदेश देने का प्रयास किया है कि सुशासन और कानून के राज से बढ़कर और कोई नहीं है।

9. संकल्प-पत्र-2023 मध्यप्रदेश की जनता को माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी भी है और विकसित मध्यप्रदेश के निर्माण का विज़न डॉक्यूमेंट भी। प्रसन्नता का विषय है कि मेरी सरकार ने संकल्प-पत्र के बिंदुओं को धरातल पर उतारने का काम प्रारंभ कर दिया है। सरकार द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 3 हजार रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4 हजार रुपए प्रति मानक बोरा कर दी गई है। इस निर्णय से 35 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहकों को 162 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त होगा। मध्यप्रदेश के मन में बसे माननीय मोदी जी की हर गारंटी को पूरा करने के उद्देश्य से संकल्प-पत्र के प्रत्येक बिंदु को समय-सीमा में क्रियान्वित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

10. मेरी सरकार अगले 7 वर्ष में मध्यप्रदेश को 45 लाख करोड़ रुपए की अर्थ-व्यवस्था बनाने और लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश से प्रतिव्यक्ति आय को दुगुना करने के लक्ष्य के

साथ कार्य कर रही है। वर्ष 2022-23 के प्रचलित भावों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद की वर्तमान वृद्धि दर 16.43% को और आगे बढ़ाने के लिए सरकार तेजी से प्रयास करेगी।

11. प्रधानमंत्री जी के सबल नेतृत्व में नये भारत की नई संसद में पारित "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" वस्तुत: भारतीय नारी की शक्ति और कीर्ति को संपूर्ण विश्व में ज्योतिर्मय करने का जयघोष है। प्रदेश में लगभग 20 वर्षों के विश्वास और विकास को आगे बढ़ाते हुए नारी उत्थान के हर संकल्प को पूरा करना मेरी सरकार की प्राथमिकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में अपने बलबूते पर आगे बढ़ने का उल्लेखनीय अवसर प्रदान किया है। सरकार द्वारा अब तक लगभग 5 लाख स्व-सहायता समूहों से 61 लाख से अधिक महिलाओं को जोड़ा जा चुका है। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिकएवं राजनैतिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से लागू की गईं केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रदेश की करोड़ों माताओं-बहनों और बेटियों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं।

12. किसानों की समृद्धि ही प्रदेश की सुख-समृद्धि का आधार है। मेरी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, समर्थन मूल्य पर उपार्जन, कृषि

अधोसंरचना निधि आदि विभिन्न किसान कल्याण योजनाओं के अंतर्गत विगत साढ़े 3 वर्षों में किसानों के खातों में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष में प्रदेश में श्रीअन्न उत्पादों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मिशन मोड में काम किया जा रहा है। प्रदेश में इस वर्ष मिलेट फसलों का कुल क्षेत्रफल 5 लाख 64 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 6 लाख 24 हजार हेक्टेयर तथा कुल उत्पादन 11 लाख 97 हजार मीट्रिक टन से बढ़कर 13 लाख 11 हजार मीट्रिक टन तक पहुंचने की संभावना है।

13. राज्य सरकार के प्रयासों से आज मध्यप्रदेश संतरा, धनिया, मसाले एवं औषधीय पौधों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश के कृषकों को रोगमुक्त और उच्च गुणवत्ता के आलू बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश की प्रथम ऐरोपोनिक यूनिट एवं टिशूकल्चर लैब की स्थापना ग्वालियर में की जा रही है। प्रदेश में 8 करोड़ रूपये से अधिक की लागत के 12 उद्यानिकी कृषक प्रशिक्षण केन्द्र बनाये गये हैं। नर्सरियों के कुशल प्रबंधन हेतु पहली बार अत्याधुनिक नर्सरी पोर्टल तैयार किया गया है।

14. मछली उत्पादन में लगातार उल्लेखनीय वृद्धि के लिये भारत सरकार द्वारा ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस में मध्यप्रदेश के सिवनी और बालाघाट जिले को उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया है।

प्रदेश में अब तक 87 हजार से अधिक मछुआ क्रेडिट कार्ड स्वीकृत करते हुए मध्यप्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है।

15. मेरी सरकार मुख्यमंत्री गौ-सेवा योजना, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदाय, चलित पशु चिकित्सा इकाई योजना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन और मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम जैसी अभिनव योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर किसानों और पशुपालकों को लाभान्वित करने का काम निरंतर कर रही है।

16. भारत सरकार के "सहकार से समृद्धि अभियान" अंतर्गत प्रदेश की 4 हजार 500 से अधिक सहकारी संस्थाओं का 145 करोड़ रुपए की लागत से कम्प्यूटरीकरण कराया जा रहा है। किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर 3 लाख रूपये तक का अल्पावधि कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के आधारभूत ढ़ाँचे को सुदृढ़ करने के लिए कृषि अधोसंरचना कोष से 1 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण सुविधा प्रदान की गई है।

17. कमजोर और वंचित वर्गों के कल्याण का संकल्प राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा, जनजातीय कल्याण के संकल्प की प्रबल अभिव्यक्ति

है। अगले 5 वर्षों में जनजातीय कल्याण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के व्यय किए जाने का लक्ष्य है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के भाई-बहनों के सर्वांगीण विकास हेतु क्रियान्वित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण हेतु राजभवन में पृथक जनजातीय प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। पेसा नियमों के क्रियान्वयन से 1 करोड़ से अधिक जनजातीय समुदाय लाभांवित हुआ है। जनजातीय समुदाय के लिए विभिन्न स्व-रोज़गार योजनाओं के माध्यम से 60 करोड़ रुपएकी सहायता प्रदान की गई है। जनजातीय सेनानियों के बलिदानों की स्मृति को अमर बनाने के लिए 2 नये संग्रहालयों का निर्माण किया जा रहा है। मेरी सरकार सभी जनजातीय विकासखंडों में सिकल सेल एनिमिया की जाँच और उपचार के मिशन को और तेजी से तथा प्रभावी रूप से क्रियान्वित करेगी। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत 10 लाख से भी अधिक लाभार्थियों को जेनेटिक काउंसिलिंग कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। मेरी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जी के वर्ष 2047 तक सिकल सेल उन्मूलन संकल्प की प्राप्ति के लिए आगामी 2 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में 37 लाख लोगों की जाँच की जावेगी।

18. प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य 1690 ग्रामों के समेकित विकास हेतु प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें मध्यप्रदेश, देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य बना

है। सागर में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का भव्य स्मारक लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जा रहा है।

19. प्रदेश के पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के 33 लाख से अधिक विद्यार्थियों को 700 करोड़ रुपए की विभिन्न छात्रवृत्तियों का लाभ दिया गया है। प्रसन्नता का विषय है कि पिछड़ा वर्ग के युवक-युवतियों को विदेश में रोज़गार दिलाने वाली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से 05 प्रशिक्षुओं का चयन जापान के निजी संस्थानों में हुआ है। प्रदेश के 51 विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदायों के समग्र कल्याण के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं, छात्रावास, बस्ती विकास, स्व-रोज़गार, कौशल प्रशिक्षण आदि विभिन्न योजनाओं का सफल संचालन किया जा रहा है।

20. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही संपूर्ण व्यक्तित्व विकास और सशक्तिकरण का प्रवेश द्वार है। यह निश्चय ही गर्व का विषय है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश प्रारंभ से ही देश का अग्रणी राज्य रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अच्छी शिक्षा की गारंटी के संकल्प का परिपालन करते हुए मेरी सरकार द्वारा लगभग 450 करोड़ रुपए की राशि से प्रदेश के सभी जिलों में चिन्हित महाविद्यालयों को "पीएम उत्कृष्टता महाविद्यालय" के रूप में उन्नयन करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। इन महाविद्यालयों में सभी

संकायों से सबंधित कोर्स संचालित किए जाएंगे तथा यहाँ सर्वसुविधायुक्त कक्षाएँ, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, खेल मैदान, ऑडिटोरियम, प्लेसमेंट सेल, ट्रेनिंग सेंटर आदि समस्त सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सभी शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों में छात्र-छात्राओं को प्राप्त होने वाली अंकसूचियों को डिजीलॉकर में अपलोड करने के सरकार के निर्णय से लाखों विद्यार्थी लाभांवित होंगे।

21. स्कूली बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए इस वित्तीय वर्ष और आगामी वित्तीय वर्ष को मिलाकर 250 से अधिक सीएम राइज स्कूलों को 10 हजार करोड़ रुपए की लागत से सर्वसुविधा संपन्न बनाया जाएगा। हर्ष का विषय है कि प्रदेश के लिए केंद्र सरकार द्वारा 416 पीएम-श्री विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। इन विद्यालयों को इस वर्ष लगभग 219 करोड़ रुपए की लागत से माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप विकसित किया जाएगा। सरकार द्वारा लगभग 50 हजार शिक्षकों की भर्ती से शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में मदद मिली है।

22. राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मंशा के अनुरूप शिक्षा के साथ-साथ कौशल विकास पर भी मेरी सरकार पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क का संचालन प्रारंभ हो चुका है। संकल्प-पत्र के अनुरूप सरकार ग्वालियर,

जबलपुर, रीवा और सागर में भी नये ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना, मध्यप्रदेश कौशल विकास परियोजना आदि के माध्यम से कौशल विकास एवं प्रतिभा प्रोत्साहन के कार्य को निरंतर आगे बढ़ाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के विज़न के अनुरूप प्रदेश में खेलों के लोकव्यापीकरण और खेल संस्कृति के विकास हेतु अधोसंरचना निर्माण, खेल स्पर्धाओं के आयोजन एवं खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण सुविधाओं की उपलब्धता के लिए मेरी सरकार कृत-संकल्पित है।

23. समय पर अपनी क्षमता एवं प्रतिभा के अनुरूप रोज़गार एवं स्व-रोज़गार प्राप्त करना न केवल युवाओं का सपना होता है, बल्कि राज्य की समृद्धि का मार्ग भी यहीं से होकर निकलता है। अत: मेरी सरकार संकल्प-पत्र के अनुरूप अगले 5 वर्षो में ढाई लाख सरकारी नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराने एवं हर परिवार में कम से कम एक रोज़गार अथवा स्व-रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लक्ष्य के साथ कार्य करेगी। प्रधानमंत्री रोज़गार मेलों की तर्ज पर प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर रोज़गार मेलों का नियमित आयोजन किए जाने का लक्ष्य है।

24. अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचाते हुए जन-जन की जिंदगी में

खुशहाली लाने का काम मेरी सरकार के लिए ईश्वर की अर्चना का माध्यम है। प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 3 करोड़ 76 लाख कार्ड जारी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 82 लाख 38 हजार से अधिक नि:शुल्क गैस कनेक्शनों ने महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाई है। जल जीवन मिशन अंतर्गत 66 लाख से अधिक परिवारों तक नल का जल पहुँच चुका है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 5 करोड़ 37 लाख लोग नि:शुल्क राशन सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्रदेश के 83 लाख से अधिक पात्र किसानों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 45 लाख से अधिक आवास निर्मित हो चुके हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ 16 हजार से अधिक पात्र हितग्राहियों को दिया जा चुका है। पी.एम. स्वनिधि योजना के माध्यम से 10 लाख से अधिक छोटे व्यवसायियों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत लगभग 19 लाख अधिकार पत्र वितरित किये जा चुके हैं। संबल योजना के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 5 लाख 25 हजार से अधिक श्रमिक लाभांवित हुए हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना के माध्यम से 2 करोड़ 75 लाख से अधिक लोगों को नाम मात्र के शुल्क पर भरपेट भोजन उपलब्ध हुआ है। मुख्यमंत्री आवासीय

भू-अधिकार योजना के अंतर्गत 2 लाख 30 हजार से अधिक लाभार्थियों को नि:शुल्क भू-खण्ड आवंटित किए गए हैं। गरीब कल्याण की ऐसी सभी योजनाओं का निरंतर प्रभावी क्रियान्वयन, मध्यप्रदेश में डबल ईंजन की सरकार की सफलता के चमत्कार की कहानी स्वयं बयान कर रहा है।

25. मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना, मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ प्रभावी ढंग से प्रदान किया जा रहा है। चिन्हित पात्र महिलाओं के लिए 450 रुपए में गैस रिफिल की योजना के अंतर्गत अब तक 22 लाख से अधिक हितग्राहियों के खातों में लगभग 220 करोड़ रुपए का अनुदान अंतरित किया गया है। प्रदेश के 121 रैन-बसेरों को सर्वसुविधायुक्त बनाया गया है और 20 नए रैन-बसेरे स्वीकृत किए गए हैं। जब तक मेरी सरकार हर गरीब, हर वंचित और हर पीड़ित के कष्टों को हरकर उन्हें उनका वाज़िब हक नहीं दिला देती, वह एक दिन भी चैन से नहीं बैठेगी।

26. दिव्यांग कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मध्यप्रदेश को वर्ष 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। प्रदेश में 47 जिलों में जिला ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड गठित किये जा चुके हैं। वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण, पुनर्वास एवं संरक्षण के लिये 77 वरिष्ठ आश्रमों का संचालन किया जा रहा है, जिससे 2200 से अधिक वरिष्ठ नागरिक लाभांवित हो रहे

हैं। मेरी सरकार द्वारा वरिष्ठ पत्रकारों को दी जाने वाली श्रद्धा निधि, बीमारियों में इलाज के लिये वित्तीय सहायता, शिक्षा ऋण, पत्रकारिता प्रशिक्षण, आवास ऋण, दुर्घटना बीमाआदि के संबंध में अनेक कल्याणकारी निर्णय लेकर लागू कर दिये गये हैं।

27. सुदृढ़ आधारभूत संरचना ही विकास का सर्वोत्तम आधार है और इस विषय में मेरी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की उस सीख का अक्षरश: अनुसरण करेगी, जो यह कहती है कि यदि शिलान्यास हमारे वादे का प्रतीक है तो लोकार्पण हमारे इरादे का। इस वर्ष राज्य सरकार 56 हजार 256 करोड़ रुपए के रिकार्ड पूंजीगत व्यय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

28. हर खेत को पानी उपलब्ध कराना मेरी सरकार का संकल्प है। सरकार के प्रयासों से प्रदेश की निर्मित सिंचाई क्षमता 47 लाख हेक्टेयर से भी अधिक हो गई है, जिसे वर्ष 2025 तक 61 लाख हेक्टेयर तक पहुँचाने का लक्ष्य है। मध्यप्रदेश के केन एवं बेतवा कछार के 10 जिलों के लिए वरदान बनी केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर दिया गया है। मेरी सरकार मध्यप्रदेश को आवंटित 18.25 MAF नर्मदा जल का संपूर्ण उपयोग वर्ष 2024 तक सुनिश्चित करने हेतु कृत-संकल्पित है। अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत 5 हजार

300 से अधिक सरोवर विकसित कर लिये गये हैं। मध्यप्रदेश इस योजना के क्रियान्वयन में देश में दूसरे स्थान पर है।

29. मेरी सरकार के प्रयासों से मध्यप्रदेश बिजली के मामले में निरंतर आत्म-निर्भर राज्य बना हुआ है। अटल गृह ज्योति योजना के अंतर्गत पात्र उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट की खपत हेतु अधिकतम 100 रुपए का बिल दिया जा रहा है। इस योजना से लगभग 103 लाख उपभोक्ता प्रतिमाह लाभान्वित हो रहे हैं। इस हेतु मेरी सरकार द्वारा लगभग 4 हजार 700 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। अटल कृषि ज्योति योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष औसतन 11 से 12 हजार करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। मेरी सरकार 1 हेक्टेयर तक भूमि और 5 हार्सपॉवर तक के कृषि पंप वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के 9 लाख से अधिक कृषकों को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय करने का काम कर रही है। इस हेतु मेरी सरकार द्वारा लगभग रुपए 5 हजार 800 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार मेरी सरकार द्वारा बिजली क्षेत्र में कुल राशि लगभग 22 हजार करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।

30. मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना में प्रथम वर्ष में 10 हजार पंप कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है। भारत सरकार की रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम योजना के क्रियान्वयन हेतु मेरी

सरकार द्वारा 24 हजार 170 करोड़ रुपए की कार्ययोजना स्वीकृत की गई है।

31. सड़कों का निर्माण और निरंतर उन्नयन प्रदेश की प्रगति की पहचान है। इस वित्तीय वर्ष में राज्य बज़ट में 9 हजार करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया गया है एवं 28 हजार करोड़ रुपए से अधिक के सड़क एवं पुल निर्माण कार्य प्रगतिरत है। प्रदेश में 14 हजार किलोमीटर से अधिक लम्बाई की सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण किया जा रहा है। राज्यव्यापी कनेक्टीविटी को और बेहतर बनाने हेतु आने वाले समय में 1 लाख किलोमीटर लम्बाई की सड़कों और 6 एक्सप्रेस वे के निर्माण किए जाने का लक्ष्य है।

32. माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार कि उनके द्वारा मध्यप्रदेश को 3 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी गई है। इनकी लोकप्रियता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस वर्ष दिसंबर के प्रथम सप्ताह में इनकी ऑक्यूपेंसी लगभग 100 प्रतिशत रही है।

33. मेरी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी का हवाई चप्पल पहनने वालों के लिए हवाई यात्राओं की सुविधा उपलब्ध कराने का सपना साकार कर रही है। दतिया हवाई पट्टी से भारत सरकार की उडान योजना के अंतर्गत हवाई सेवाएं शीघ्र संचालित होना प्रारंभ होंगी। सिंगरौली जिले में नई हवाई पट्टी निर्मित हो चुकी

है। प्रदेश के 11 जिलों की हवाई पट्टियों को निर्धारित शुल्क पर विभिन्न उड्डयन गतिविधियों के संचालन हेतु आवंटित किया गया है। ग्वालियर स्थित विमानतल का विस्तार एवं विकास किया जा रहा है। भूतभावन महाकाल की नगरी उज्जैन एवं विंध्य की नगरी रीवा में स्थित हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित किये जाने का लक्ष्य है।

34. नगरोदय और ग्रामोदय के साथ अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करना मेरी सरकार की प्राथमिकता है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 6 हजार 500 करोड़ से अधिक के कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत इस वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष को मिलाकर 1 हजार 700 करोड़ रुपए की लागत के कार्य किए जाएंगे। भारत सरकार की अमृत-2 योजना से मध्यप्रदेश के 33 शहरों में 6 हजार 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के जल आपूर्ति एवं सीवरेज परियोजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। भोपाल एवं इन्दौर की तर्ज पर जबलपुर और ग्वालियर के लिए मेट्रो रेल का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। नमामि नर्मदे योजना के अंतर्गत जबलपुर में 15 किलोमीटर का नर्मदा पथ और नर्मदा वन विकसित किए जाने की योजना है। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत भारत सरकार से क्षिप्रा नदी के शुद्धिकरण हेतु 611 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसका कार्य शीघ्र

प्रारंभ किया जाएगा। प्रदेश के 3 शहरों- इन्दौर, भोपाल एवं जबलपुर में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता पर ई-चार्जिंग अधोसंरचना का विकास किया जा रहा है। मध्यप्रदेश स्वच्छ सर्वेक्षण- 2023 में भी देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनकर उभरने के लिए कृत-संकल्पित है।

35. मध्यप्रदेश की आत्मा ग्रामों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों के परिवारों को केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाकर उन्हें स्वयं पूर्ण और समृद्ध परिवार बनाना मेरी सरकार का मिशन है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से मेरी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में बारहमासी सड़कों का जाल बिछा दिया है। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत इस वर्ष औसतन 20 करोड़ मानव दिवसों का सृजन सरकार का लक्ष्य है। प्रदेश के 50 हजार से अधिक ग्राम ओ.डी.एफ. प्लस हो चुके हैं। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत दर्ज 65 लाख विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन का लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्र में 230 करोड़ रुपए के जल संरक्षण और संवर्द्धन के कार्य किए गए हैं।

36. मध्यप्रदेश का हर नागरिक निरोगी रहे और दूरस्थ अँचलों तक जाँच एवं उपचार की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हों, यही मेरी

सरकार का लक्ष्य है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रतिदिन औसतन 4 हजार हितग्राहियों का लगभग 4 करोड़ रूपये के व्यय से नि:शुल्क उपचार किया जा रहा हैं। प्रदेश में 11 हजार 800 से अधिक आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर क्रियाशील हैं, जिनमें अब तक 2 करोड़ से भी अधिक लोगों को उपचार एवं परामर्श सेवाएं दी जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 562 आयुष हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर भी क्रियाशील हो चुके हैं। क्षय रोग उन्मूलन में उत्कृष्ट कार्य के लिये मध्यप्रदेश के 13 जिलों को भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। राज्य का प्रथम नवजात शिशु एवं बाल चिकित्सा संसाधन केन्द्र भोपाल में स्थापित किया गया है।

37. प्रदेश में भारत सरकार के सहयोग से 7 स्वशासी एवं 1 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की गई है एवं 150 एम.बी.बी.एस. सीट प्रवेश क्षमता के 6 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जा रहे है। इसी प्रकार राज्य बजट से 100 MBBS सीट प्रवेश क्षमता के 04 जिलों में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापना की प्रशासकीय स्वीकृति एवं 09 जिलों में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय स्थापना की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। भोपाल गैस त्रासदी पीड़ित लगभग 4 हजार 500 कल्याणी बहनों के लिए 1 हजार रूपये प्रतिमाह पेंशन पुन: प्रारंभ की गई है।

38. मेरी सरकार उद्योगों के विकास और निवेश संवर्द्धन के लिये प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। प्रदेश से वर्ष 2022-23 में रिकार्ड 65 हजार करोड़ रूपये से अधिक का निर्यात हुआ है। राज्य में 1 लाख 25 हजार एकड़ से अधिक का लैण्ड बैंक उद्योगों की स्थापना के लिये उपलब्ध है। प्रदेश में 10 फूड पार्क, 5 आईटी एस.ई.जेड, 2 स्पाइस पार्क, 2 प्लास्टिक पार्क, 1 मेडिकल डिवाइस पार्क, 1 पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन, 1 पीएम मित्र पार्क, 1 फुटवियर पार्क, 1 सिल्क टेक पार्क और महिला उद्यमियों के लिये डेडिकेटेड पार्क का निर्माण राज्य की उद्योग हितैषी नीतियों की बड़ी सफलता के परिचायक हैं। प्रदेश में 7 नए बड़े निवेश क्षेत्र और औद्योगिक कॉरिडोर स्थापित किये जा रहे हैं। भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में साइंस सिटी, लगभग 200 एकड़ क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्युफेक्चरिंग क्लस्टर तथा बायोटेक पार्क एवं बायो इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना का लक्ष्य है।

39. सरकार के प्रयासों और प्रोत्साहन से प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 3 हजार 700 से भी अधिक हो गई है। मेरी सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में स्टार्ट-अप की संख्या को 10 हजार तक ले जाना है। इन्दौर में डेटा सेन्टर पार्क और स्टार्ट-अप पार्क निर्माण के साथ-साथ सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिये 10 नए MSME क्लस्टर विकसित किये जाने का लक्ष्य है।

मेरी सरकार MSME इकाइयों के लिये सिंगल विंडो मैकेनिज्म पर समर्थन पोर्टल स्थापित करेगी, जिससे विशेषकर दूरस्थ अँचलों की MSME को आवश्यक सुविधाएं ऑनलाईन एवं पारदर्शी तरीके से प्राप्त हो सकें। हस्तशिल्प उत्पाद, ODOP उत्पाद, जीआई उत्पाद, और स्थानीय उत्पादों के प्रचार एवं विक्रय के लिए वन स्टॉप मार्केट प्लेस के रूप में देश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में प्रारंभ किये जाने का लक्ष्य है।

40. मध्यप्रदेश शांति का टापू है और ऐसा ही सदा बना रहे, इसके लिये राज्य सरकार कृत संकल्पित है। मेरी सरकार मध्यप्रदेश में अपराधों के नियंत्रण और प्रधानमंत्रीजी की स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा को मूर्तरूप देने के लिए निरंतर परिणाममूलक कार्य करेगी। प्रत्येक प्रकार के अपराध पर सख्ती से नियंत्रण किया जायेगा। मेरी सरकार ने राष्ट्रीय पर्वों, मध्यप्रदेश स्थापना दिवस आदि गरिमामय समारोहों को ध्यान में रखते हुए हर जिले में पुलिस बैंड तैयार करने का निर्णय लिया है।

41. मध्यप्रदेश केवल शांति का ही नहीं बल्कि जैव-विविधता का भी टापू है। माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रारंभ महत्वाकांक्षी चीता परियोजना मध्यप्रदेश में सफल रही है। यहाँ देश की पहली चीता सफारी भी स्थापित की जायेगी। वन्य प्राणी संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मेरी सरकार द्वारा वीरांगना रानी दुर्गावती टाईगर रिजर्व का गठन किया गया है।

चित्रकूट, खजुराहो, उज्जैन और भोपाल में सांस्कृतिक वनों का निर्माण किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करने के उद्देश्य से दुनिया का सबसे बड़ा पानी पर तैरते ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पॉवर प्रोजेक्ट अंतर्गत लगभग 1700 करोड़ रूपये के कार्य प्रगति पर है और मार्च 2024 तक प्रथम चरण पूर्ण करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत 45 हजार सौर ऊर्जा पंपों को स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए प्रारंभ किए गए "ऊर्जा साक्षरता अभियान" से प्रदेश के 14 लाख नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मिशन लाइफ के अंतर्गत इस वर्ष 2 हजार से अधिक वालेंटियर्स को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य है।

42. मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां नागरिकों को लोक सेवाएँ प्रदान करने की कानूनी गारंटी दी गई है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत 691 सेवाएं जोड़ी जा चुकीं हैं। समाधान एक दिवस, सी.एम. हेल्प लाईन, महिला हेल्प लाईन, सी.एम. जनसेवा, दिव्यांग हेल्प लाईन, मान्य अनुमोदन की व्यवस्था, सी.एम. डेशबोर्ड आदि अनेक पहलों के कारण मध्यप्रदेश, सुशासन की दृष्टि से देश का अग्रणी राज्य बना हुआ है। भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी को प्रभावी रूप से

क्रियान्वित करने के लिए मध्यप्रदेश क्षमता निर्माण नीति लागू कर दी गई है। प्रदेश के 54 विभागों, 98 विभागाध्यक्ष कार्यालयों, 3 संभाग आयुक्त कार्यालयों, 22 कलेक्टर कार्यालयों और 65 तहसील कार्यालय में ई-ऑफिस परियोजना सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। अनुपयोगी, निष्प्रभावी एवं अप्रचलित श्रेणी के 900 से अधिक कानूनों को निरसित करने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकीं हैं। नवगठित लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के माध्यम से परिसंपत्तियों का प्रभावी प्रबंधन एवं निर्वर्तन किया गया है। इस वर्ष प्रदेश की जेलों में बंद 3 लाख से अधिक बंदियों की पेशियाँ वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से कराई गई हैं। नई रिहाई नीति के अंतर्गत गणतंत्र दिवस, अंबेडकर जयंती, स्वतंत्रता दिवस एवं गांधी जयंती के अवसर पर 563 बंदियों को रिहा किया गया है।

43. खनिज ब्लॉकों की नीलामी में मध्यप्रदेश ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारत सरकार के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में राज्य के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए नीति आयोग द्वारा प्रदेश के 8 आकांक्षी जिलों को अभी तक 71 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई है। मेरी सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिले में ड्राईविंग ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार के वाहन एवं सारथी पोर्टल के माध्यम से राज्य में चिन्हित सेवाएं फेसलेस तरीके से

आम जनता को प्रदान की जा रही हैं। लोगों के जीवन को तनावमुक्त और खुशहाल बनाने की दृष्टि से आनन्द विभाग के माध्यम से संचालित विभिन्न कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा।

44. मेरी सरकार प्रदेश में कला, संस्कृति एवं साहित्य के विकास, संरक्षण एवं संवर्धन एवं कलाकारों-साहित्यकारों के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध एवं संवेदनशील है। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के कायाकल्प की तर्ज पर मध्यप्रदेश में श्री महाकाल महालोक परिसर का स्वरूप भव्य और दिव्य बनाया गया है। आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट की एकात्मता प्रतिमा, अद्वैत वेदांत के दर्शन का अद्वितीय आलंबन बन गई है। प्रदेश में अध्यात्म, संस्कृति और पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए 18 विभिन्न महालोकों का निर्माण एवं विकास का लक्ष्य है। भारत सरकार के सहयोग से हस्तशिल्प हाथकरघा पर आधारित प्रदेश का पहला पर्यटन स्थल प्राणपुर चन्देरी में प्रारम्भ किया जा रहा है। हनुवंतिया का जल-महोत्सव, गांधीसागर का फ्लोटिंग फेस्टिवल और चंदेरी की टेंट सिटी देश ही नहीं, दुनियाभर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के अंतर्गत इस वर्ष भारत गौरव पर्यटन ट्रेनों के द्वारा प्रदेश के 18 हजार से अधिक वरिष्ठ

नागरिकों को तीर्थ यात्रा और 700 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को वायुयान से तीर्थ यात्रा कराई गई है।

45. एक समय था जब देश में मध्यप्रदेश की छवि एक बीमारू राज्य की हुआ करती थी। विगत लगभग 2 दशकों में जनता के अपार सहयोग और सरकार के अथक परिश्रम से पिछड़ेपन के इस कलंक को धोकर मध्यप्रदेश का नाम देश के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में शुमार हुआ है। लेकिन यह विकास और जनकल्याण की महायात्रा का एक पड़ाव मात्र है, मंजिल नहीं। मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री स्वयं को जनता का मुख्य सेवक मानते हैं और वे पदभार ग्रहण करते ही जनसेवा में 24 घंटे, सातों दिन जुट गए हैं। मेरी सरकार का भविष्य का विजन बिलकुल स्पष्ट है- वर्ष 2047 के विकसित भारत के लिए विकसित मध्यप्रदेश का निर्माण। मेरी सरकार प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा संकल्प-पत्र के रूप में मध्यप्रदेश की जनता को दी गई हर गारंटी को समय-सीमा में पूरा करने के लिए बिना थके और बिना रूके कार्य करेगी। संकल्प-पत्र-2023 विकसित मध्यप्रदेश- 2047 का सशक्त आधार बनेगा।

46. आज माननीय प्रधानमंत्रीजी देश के ही नहीं, बल्कि विश्व के सर्वमान्य और सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, जिनका कुशल नेतृत्व सभी को यह विश्वास दिलाता है कि 21वीं सदी सचमुच भारत की सदी है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं-"यही समय है, सही समय

है।" अमृतकाल में विकसित और आत्म-निर्भर भारत के विश्व पटल पर उदय का प्रतीक बने, भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने- माननीय प्रधानमंत्री जी इस महान लक्ष्य की पूर्ति के लिये दिन-रात कार्य कर रहे हैं। मेरी सरकार भी प्रधानमंत्री जी के अहर्निश जनसेवा के मार्ग का अनुसरण करते हुए मध्यप्रदेश को विकास और प्रगति की नई ऊँचाईयों पर ले जाएगी।

47. चाहे अर्थ-व्यवस्था में तेज गति से वृद्धि हो या फिर अधोसंरचना का चौतरफा विस्तार, चाहे प्रदेश को स्वस्थ रखना हो या फिर शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण, चाहे कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाना हो या फिर सुशासन की जड़ें मजबूत करना, चाहे गरीबों और कमजोर वर्गों का कल्याण हो या फिर किसानों और महिलाओं का सशक्तिकरण, चाहे युवाओं के लिए अवसरों का निर्माण हो या फिर उद्योगों में निवेश के लिए वातावरण का निर्माण और चाहे आध्यात्म व संस्कृति के साथ कदम से कदम मिलाना हो या फिर पर्यटन व पर्यावरण के साथ आगे कदम बढ़ाना- हर क्षेत्र में, हर वर्ग के लिए हर प्रकार से विकास और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना ही मेरी सरकार का राजधर्म होगा।

48. इस आशा और विश्वास के साथ, कि मध्यप्रदेश की समृद्ध और जीवंत लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप अपने कर्तव्यों का

निर्वहन करते हुए सभी अपने सार्वजनिक जीवन के प्रत्येक क्षण को प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए अर्पित कर एक नए विकसित और आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश की आधारशिला रखेंगे, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

बहुत बहुत धन्यवाद

।। जय हिन्द, जय मध्यप्रदेश।।

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल—2023